International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

Original Article

भारत-भूटान संबंध: ऐतिहासिक विकास, सामरिक महत्व एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य

डॉ. अवधेश प्रसाद

सहायक प्राचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,

एम. एम. महिला महाविद्यालय, आरा

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

Manuscript ID:
IJAAR-130608
ISSN: 2347-7075
Impact Factor – 8.141

Volume - 13
Issue - 6
July – August 2026
Pp. 56 - 67

Submitted: 15 July 2026
Revised: 27 July 2026
Accepted: 1 August 2026
Published: 10 August 2026

Corresponding Author:
डॉ. अवधेश प्रसाद

Quick Response Code:

Website: https://ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.21900044

DOI Link:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21900044

सारांश:

भारत और भूटान के संबंध दक्षिण एशिया के सबसे स्थिर, विश्वासपूर्ण तथा पारस्परिक सहयोग पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों में गिने जाते हैं। इन संबंधों की ऐतिहासिक जड़ें अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और भूटान के बीच हुए संपर्कों से जुड़ी हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1949 की भारत-भूटान मैत्री संधि ने दोनों देशों के संबंधों को औपचारिक आधार प्रदान किया, जबकि 2007 में संधि के संशोधन ने भूटान की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति को और अधिक सुदृढ़ किया। वर्तमान में दोनों देशों के संबंध समानता, परस्पर सम्मान, सुरक्षा सहयोग तथा साझा विकास की भावना पर आधारित हैं।

*यह शोध-पत्र भारत-भूटान संबंधों के ऐतिहासिक विकास, सामरिक महत्व तथा समकालीन आयामों का विश्लेषण करता है। अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों, सरकारी दस्तावेजों, शोध-पत्रों, नीति-रिपोर्टों तथा आधिकारिक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, प्रमुख विकास सहयोगी तथा जलविद्युत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण निवेशक है। भूटान के कुल निर्यात का लगभग **90–98 प्रतिशत** और आयात का लगभग **80–90 प्रतिशत** भारत से संबंधित रहा है। 1961 से आरंभ हुई पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दोनों देशों के बीच जलविद्युत सहयोग, सीमा सुरक्षा, भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल तथा डोकलाम (2017) जैसी घटनाओं ने उनके सामरिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किया है।*

समकालीन परिप्रेक्ष्य में चीन की बढ़ती सक्रियता, सीमा विवाद, क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा भूटान की संतुलित विदेश नीति भारत-भूटान संबंधों के लिए नई चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करती हैं। भारत की "Neighbourhood First" नीति तथा "Act East" दृष्टिकोण ने दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति प्रदान की है। निष्कर्षतः, भारत-भूटान संबंध केवल पारंपरिक मैत्री तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे दक्षिण एशिया में स्थिरता, सतत विकास, सामरिक संतुलन तथा क्षेत्रीय सहयोग के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित हुए हैं। भविष्य में पारस्परिक विश्वास, आर्थिक

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

विविधीकरण, हरित ऊर्जा तथा डिजिटल सहयोग इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे।

मुख्य शब्द : भारत-भूटान संबंध, ऐतिहासिक विकास, सामरिक महत्व, जलविद्युत सहयोग, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, दक्षिण एशिया।

Creative Commons

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*

OPEN ACCESS

How to cite this article:
डॉ. अवधेश प्रसाद. (2026). भारत-भूटान संबंध: ऐतिहासिक विकास, सामरिक महत्व एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य. International Journal of Advance and Applied Research, 13(6), 56 – 67.
https://doi.org/10.5281/zenodo.21900044

परिचय:

भारत और भूटान के संबंध दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन, स्थिर तथा विश्वास-आधारित द्विपक्षीय संबंधों में से एक हैं। भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक समानता, बौद्ध परंपरा, ऐतिहासिक संपर्क तथा साझा सामरिक हितों ने दोनों देशों के संबंधों को समय के साथ और अधिक सुदृढ़ बनाया है। यद्यपि भारत और भूटान के औपचारिक राजनयिक संबंध 1968 में स्थापित हुए, किंतु दोनों देशों के ऐतिहासिक संपर्क अठारहवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी और भूटान के बीच हुए व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंधों से जुड़े रहे हैं। स्वतंत्र भारत और भूटान के बीच 8 अगस्त 1949 को संपन्न **भारत-भूटान मैत्री संधि** ने आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला रखी। वर्ष 2007 में इस संधि में संशोधन कर संबंधों को समान संप्रभुता, परस्पर सम्मान और सहयोग के सिद्धांतों पर पुनर्परिभाषित किया गया, जिससे भूटान की स्वतंत्र विदेश नीति को और अधिक सुदृढ़ता मिली।

भारत, भूटान का सबसे बड़ा विकास सहयोगी, प्रमुख व्यापारिक साझेदार तथा जलविद्युत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण निवेशक है। भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजनाओं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण में भारत का उल्लेखनीय योगदान रहा है। दोनों देशों के मध्य जलविद्युत परियोजनाएँ न केवल आर्थिक सहयोग का आधार हैं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। साथ ही, भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल, सीमा प्रबंधन तथा डोकलाम संकट (2017) जैसे घटनाक्रम यह स्पष्ट करते हैं कि भारत-भूटान संबंधों का सामरिक आयाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समकालीन वैश्विक एवं परिदृश्य में चीन की बढ़ती सक्रियता, हिमालयी भू-राजनीति, सीमा विवाद तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति-संतुलन की बदलती परिस्थितियों ने भारत-भूटान संबंधों को नई प्रासंगिकता प्रदान की है। भारत की **"Neighbourhood First"** नीति और **"Act East Policy"** के संदर्भ में भूटान एक विश्वसनीय और रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरकर सामने आया है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य भारत-भूटान संबंधों के ऐतिहासिक विकास, सामरिक महत्व तथा समकालीन आयामों का विश्लेषण करना तथा यह मूल्यांकन करना है कि बदलते भू-राजनीतिक परिवेश में दोनों देशों के संबंध किस प्रकार दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता, सतत विकास और क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ कर रहे हैं।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/*
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

साहित्य समीक्षा:

भारत-भूटान संबंधों पर उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक, सामरिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। **उत्तम लामा (2021)** ने अपने अध्ययन में भारत-भूटान संबंधों के ऐतिहासिक विकास (1774–2019) का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक संबंध व्यापार-केंद्रित थे, जबकि स्वतंत्रता के बाद उनका स्वरूप सामरिक, राजनीतिक तथा विकासात्मक सहयोग की ओर परिवर्तित हुआ। **हर्ष वी. पंत** का मत है कि भूटान भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का सबसे सफल उदाहरण है, जहाँ पारस्परिक विश्वास और साझा सुरक्षा हित संबंधों की आधारशिला हैं। **एस. डी. मुनी** ने भारत-भूटान संबंधों को हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा, चीन के बढ़ते प्रभाव तथा क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में विश्लेषित किया है।

स्टोबदान (2014) का तर्क है कि भारत द्वारा भूटान में जलविद्युत, अवसंरचना तथा पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया निवेश दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाता है, यद्यपि इससे भूटान की आर्थिक निर्भरता पर भी बहस होती रही है। वहीं **राजपूत** ने 1949 एवं 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधियों के विकास का विश्लेषण करते हुए इन्हें द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण मील के पत्थर बताया है। उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन ऐतिहासिक, सुरक्षा एवं आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित हैं, जबकि समकालीन भू-राजनीतिक परिवर्तनों, डिजिटल सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा **विकसित भारत 2047** के संदर्भ में भारत-भूटान संबंधों का समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है। प्रस्तुत शोध इसी शोध-अंतर को संबोधित करने का प्रयास करता है।

आँकड़े एवं अनुसंधान पद्धति:

प्रस्तुत शोध-पत्र **"भारत-भूटान संबंध: ऐतिहासिक विकास, सामरिक महत्व एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य"** गुणात्मक एवं वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों के ऐतिहासिक विकास, सामरिक महत्व, आर्थिक सहयोग तथा समकालीन भू-राजनीतिक परिवर्तनों परिणाम एवं परिचय का समग्र विश्लेषण करना है। इस शोध में प्राथमिक आँकड़ों के स्थान पर विश्वसनीय **द्वितीयक स्रोतों** का उपयोग किया गया है।

अध्ययन के लिए भारत सरकार के **विदेश मंत्रालय**, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**, **भारत स्थित भूटान दूतावास**, **भूटान सरकार**, **रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया**, **विश्व बैंक**, **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष**, **एशियाई विकास बैंक** तथा **संयुक्त राष्ट्र** के आधिकारिक प्रकाशनों, वार्षिक प्रतिवेदनों एवं सांख्यिकीय रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त समकालीन शोध-पत्रों, पुस्तकों, नीति-रिपोर्टों, जर्नल लेखों तथा थिंक-टैंक संस्थानों जैसे **Observer Research Foundation (ORF)**, **Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA)** एवं **ICRIER** के अध्ययनों का भी संदर्भ लिया गया है।

शोध में 1949 एवं 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधियों, पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की विकास सहायता, जलविद्युत परियोजनाओं, व्यापारिक आँकड़ों, सीमा सुरक्षा

सहयोग तथा डोकलाम जैसे प्रमुख घटनाक्रमों का तुलनात्मक एवं विषयवस्तु विश्लेषण किया गया है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा भूटान के कुल व्यापार का अधिकांश भाग भारत के साथ होता है। भारत द्वारा चुखा, ताला, कुरिचू, मांगदेछू जैसी जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से दी गई विकास सहायता का भी विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन में ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। संकलित तथ्यों एवं आँकड़ों का विश्लेषण वर्तमान क्षेत्रीय एवं वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य, भारत की **पड़ोसी प्रथम नीति**, चीन के बढ़ते प्रभाव तथा दक्षिण एशिया की सामरिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया है। इस प्रकार प्रयुक्त अनुसंधान पद्धति भारत-भूटान संबंधों के बहुआयामी स्वरूप का वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।

परिणाम एवं परिचर्चा:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

भारत और भूटान के संबंधों का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है तथा इसकी जड़ें सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक और भौगोलिक संपर्कों में निहित हैं। प्राचीन काल से ही हिमालयी मार्गों के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार, बौद्ध धर्म का प्रसार तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता रहा। अठारहवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी और भूटान के बीच औपचारिक संपर्क स्थापित हुए। **1774 की शांति संधि** ने दोनों पक्षों के बीच व्यापार और राजनीतिक संबंधों की आधारशिला रखी। इसके बाद **1865 की सिंचुला संधि** के अंतर्गत भूटान को डुआर्स क्षेत्र ब्रिटिश भारत को सौंपना पड़ा, जिसके बदले उसे वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में तिब्बत में चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण हिमालयी क्षेत्र का सामरिक महत्व बढ़ गया। **1910 की पुनाखा संधि** के अंतर्गत ब्रिटिश भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया, जबकि भूटान ने अपने विदेश संबंधों में ब्रिटिश सरकार के मार्गदर्शन को स्वीकार किया। इस व्यवस्था ने भूटान की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए उसकी बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित की।

भारत की स्वतंत्रता के बाद **8 अगस्त 1949** को भारत और भूटान के बीच **शांति एवं मैत्री संधि** पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने दोनों देशों के संबंधों को औपचारिक रूप दिया तथा शांति, मैत्री, मुक्त व्यापार और सुरक्षा सहयोग को संस्थागत आधार प्रदान किया। 1950 में तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बाद भारत और भूटान के सामरिक संबंध और अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 1961 से भारत ने भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान करनी प्रारंभ की, जिससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा जलविद्युत जैसे क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ।

भूटान ने **1971 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता** प्राप्त की, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण समर्थन दिया। इसके बाद भूटान ने धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विस्तार किया। वर्ष **2007 में भारत-भूटान मैत्री संधि में संशोधन** किया गया, जिसके तहत भारत द्वारा भूटान की विदेश नीति का मार्गदर्शन करने वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया और

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | Website: https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

दोनों देशों के संबंध समान संप्रभुता, परस्पर सम्मान तथा साझा राष्ट्रीय हितों के आधार पर पुनर्परिभाषित किए गए। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से भारत-भूटान संबंध व्यापारिक संपर्कों से विकसित होकर आज एक व्यापक **रणनीतिक, आर्थिक, विकासात्मक और विश्वास-आधारित साझेदारी** के रूप में स्थापित हो चुके हैं।

सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग:

भारत और भूटान के संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आयाम **सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग** है। हिमालयी क्षेत्र में स्थित भूटान भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, क्योंकि यह भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों और चीन (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र) के बीच एक संवेदनशील बफर राज्य के रूप में स्थित है। लगभग **699 किलोमीटर** लंबी भूटान-चीन सीमा तथा **605 किलोमीटर** लंबी भारत-भूटान सीमा दोनों देशों के सुरक्षा हितों को परस्पर जोड़ती है। इसलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भूटान की संप्रभुता एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

1949 की भारत-भूटान मैत्री संधि ने सुरक्षा सहयोग की आधारशिला रखी, जिसे **2007 की संशोधित संधि** में समान संप्रभुता और पारस्परिक राष्ट्रीय हितों के अनुरूप पुनर्परिभाषित किया गया। संशोधित संधि के अनुसार दोनों देश एक-दूसरे की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से संबंधित विषयों पर घनिष्ठ सहयोग करेंगे तथा किसी भी देश को अपनी भूमि का उपयोग दूसरे देश के विरुद्ध नहीं करने देंगे।

भारत का **Indian Military Training Team (IMTRAT)**, जो 1961 से भूटान में कार्यरत है, रॉयल भूटान आर्मी को सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त **प्रोजेक्ट DANTAK** के माध्यम से भारत ने भूटान में सड़कों, पुलों और सामरिक अवसंरचना का निर्माण कर दोनों देशों की सुरक्षा तथा संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ किया है।

वर्ष **2003 में "ऑपरेशन ऑल क्लियर"** के दौरान रॉयल भूटान आर्मी ने भारत के सहयोग से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड तथा के.एल.ओ. जैसे उग्रवादी संगठनों के शिविरों को भूटान की भूमि से समाप्त किया। इस अभियान ने दोनों देशों के बीच आतंकवाद-विरोधी सहयोग और पारस्परिक विश्वास को नई मजबूती प्रदान की।

2017 का डोकलाम गतिरोध भारत-भूटान सामरिक सहयोग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। चीन द्वारा डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण के प्रयास का भारत ने भूटान के अनुरोध पर विरोध किया। लगभग **73 दिनों** तक चले इस गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान ने यह स्पष्ट किया कि भारत भूटान की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में चीन की बढ़ती गतिविधियाँ, सीमा विवाद, साइबर सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन जैसी चुनौतियों ने भारत-भूटान सुरक्षा सहयोग को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। नियमित उच्चस्तरीय सैन्य वार्ताएँ, संयुक्त प्रशिक्षण, खुफिया सहयोग तथा सीमा प्रबंधन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं। इस प्रकार भारत-भूटान का सुरक्षा सहयोग केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया की शांति, स्थिरता और सामरिक संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण आधार है।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/*
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:

भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का सबसे सशक्त आधार **आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग** है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, प्रमुख विकास सहयोगी तथा विदेशी निवेश का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूटान की स्थल-रुद्ध भौगोलिक स्थिति के कारण उसका अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत के माध्यम से संचालित होता है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था, सीमा-पार संपर्क तथा पारस्परिक आर्थिक सहयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ किया है।

1949 की भारत-भूटान मैत्री संधि तथा उसके बाद हुए व्यापार एवं वाणिज्य समझौतों ने दोनों देशों के बीच व्यापार को संस्थागत आधार प्रदान किया। **1995 के भारत-भूटान व्यापार समझौते** तथा इसके बाद के संशोधनों ने वस्तुओं के निर्बाध आवागमन, सीमा शुल्क में रियायत तथा व्यापारिक सुविधाओं का विस्तार किया। वर्तमान में जयगाँव–फुंटशोलिंग सीमा दोनों देशों के बीच व्यापार का सबसे प्रमुख प्रवेश द्वार है, जहाँ से लगभग **70 प्रतिशत से अधिक** द्विपक्षीय व्यापार संचालित होता है।

भारत भूटान के कुल व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार भूटान के कुल निर्यात का लगभग **90–95 प्रतिशत** तथा आयात का लगभग **80–90 प्रतिशत** भारत के साथ होता है। वर्ष **2018–19** में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार **1.02 अरब अमेरिकी डॉलर** से अधिक रहा। भारत से भूटान को मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, वाहन, लौह एवं इस्पात, खाद्यान्न, औषधियाँ तथा निर्माण सामग्री का निर्यात किया जाता है, जबकि भूटान से भारत मुख्यतः **जलविद्युत (बिजली), फेरोसिलिकॉन, सीमेंट, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बाइड, ताँबा तथा लकड़ी आधारित उत्पाद** आयात करता है।

भारत-भूटान आर्थिक सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र **जलविद्युत** है। चुखा (336 मेगावाट), कुरिचू (60 मेगावाट), ताला (1,020 मेगावाट) तथा मांगदेछू (720 मेगावाट) जैसी परियोजनाएँ दोनों देशों की सफल विकास साझेदारी का उदाहरण हैं। इन परियोजनाओं से उत्पादित अधिकांश विद्युत भारत को निर्यात की जाती है, जिससे भूटान की सरकारी आय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है तथा भारत की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है।

भारत 1961 से भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख विकास सहयोगी रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, ग्रामीण विकास तथा अवसंरचना निर्माण में भारत ने निरंतर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल पहल ने क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और आर्थिक एकीकरण को नई दिशा प्रदान की है।

यद्यपि आर्थिक सहयोग निरंतर मजबूत हुआ है, फिर भी भूटान की भारतीय बाजार पर अत्यधिक निर्भरता, व्यापार असंतुलन, जलविद्युत परियोजनाओं में लागत वृद्धि तथा चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव जैसी चुनौतियाँ भविष्य में संतुलित आर्थिक नीति की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। इसके बावजूद भारत और भूटान की आर्थिक साझेदारी आज दक्षिण एशिया में **विश्वास, परस्पर लाभ और सतत विकास** पर आधारित सहयोग का एक सफल मॉडल मानी जाती है।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | Website: https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

जलविद्युत सहयोग:

भारत-भूटान संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आयाम **जलविद्युत सहयोग** है। हिमालयी नदियों की प्रचुर जल क्षमता के कारण भूटान जलविद्युत उत्पादन की अपार संभावनाओं वाला देश है, जबकि भारत ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार कर रहा है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच जलविद्युत क्षेत्र में सहयोग परस्पर लाभकारी साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।

भारत ने 1961 से भूटान की विकास योजनाओं के साथ-साथ जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में वित्तीय, तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग प्रदान किया है। **चुखा (336 मेगावाट)**, **कुरिचू (60 मेगावाट)**, **ताला (1,020 मेगावाट)** और **मांगदेछू (720 मेगावाट)** जैसी प्रमुख परियोजनाएँ भारत की सहायता से विकसित की गई हैं। वर्तमान में **पुनात्सांगछू-I (1,200 मेगावाट)**, **पुनात्सांगछू-II (1,020 मेगावाट)** तथा **खोलोंगछू (600 मेगावाट)** जैसी परियोजनाएँ भी दोनों देशों के सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। इन परियोजनाओं से उत्पादित अधिकांश विद्युत भारत को निर्यात की जाती है, जिससे भूटान की राष्ट्रीय आय और विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

जलविद्युत क्षेत्र भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। भूटान के कुल निर्यात में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है और भारत इसका सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरी ओर, भारत को स्वच्छ, विश्वसनीय और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी बल मिलता है। इस प्रकार यह सहयोग **"विन-विन साझेदारी"** का उत्कृष्ट उदाहरण है।

हालाँकि, हाल के वर्षों में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जिनमें परियोजनाओं की लागत में वृद्धि, निर्माण में विलंब, ऋण भार, पर्यावरणीय प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम प्रमुख हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु दोनों देशों ने संयुक्त परियोजना प्रबंधन, वित्तीय पुनर्गठन, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया है।

समग्रतः, भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख आधार बन चुका है। भविष्य में हरित ऊर्जा, सीमा-पार विद्युत व्यापार तथा क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड के विकास के माध्यम से यह सहयोग दोनों देशों के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध:

भारत और भूटान के राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध दक्षिण एशिया में पारस्परिक विश्वास, संप्रभु समानता तथा दीर्घकालिक सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध **1968** में स्थापित हुए, जबकि स्वतंत्र भारत और भूटान के बीच **1949 की भारत-भूटान मैत्री संधि** ने आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला रखी। इस संधि को **2007** में संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत भूटान की विदेश नीति पर भारत के मार्गदर्शन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दोनों देशों के संबंधों

को समान संप्रभुता, पारस्परिक सम्मान और साझा राष्ट्रीय हितों के आधार पर पुनर्परिभाषित किया गया।

भारत ने भूटान की अंतरराष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। **1971 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता** प्राप्त करने में भारत ने भूटान का सक्रिय समर्थन किया। इसके अतिरिक्त, भारत ने भूटान को **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन**, **बिम्सटेक** तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों पर प्रभावी भूमिका निभाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान किया है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, क्षेत्रीय संपर्क, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी समान दृष्टिकोण रखते हैं।

भारत की **"पड़ोसी प्रथम नीति"** तथा भूटान की संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान की है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं प्रधानमंत्रियों के बीच नियमित उच्चस्तरीय यात्राएँ इस विशेष संबंध की प्रमुख विशेषता हैं। **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने प्रथम विदेश दौरे के लिए भूटान का चयन किया**, जो दोनों देशों के संबंधों के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। इसके पश्चात 2019 और 2024 में भी उच्चस्तरीय यात्राओं तथा द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना तथा सीमा प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ किया गया। वर्ष **2024 में भूटान के राजा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो (Order of the Dragon King)"**, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से सम्मानित किया जाना दोनों देशों के गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है।

यद्यपि भूटान ने समय के साथ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विस्तार किया है और विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं, फिर भी भारत उसकी विदेश नीति का सबसे विश्वसनीय और निकटतम साझेदार बना हुआ है। वर्तमान में बदलते वैश्विक एवं क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य, विशेषकर चीन की बढ़ती सक्रियता, के बीच भारत और भूटान के राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता, विश्वास तथा क्षेत्रीय सहयोग के महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं।

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंध:

भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंध सदियों पुराने ऐतिहासिक, धार्मिक और सभ्यतागत संपर्कों पर आधारित हैं। दोनों देशों के संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी साझा **बौद्ध सांस्कृतिक विरासत**, पारस्परिक सम्मान तथा लोगों के बीच गहरे सामाजिक संबंध हैं। भूटान में महायान बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव है, जबकि भारत भगवान बुद्ध की जन्मभूमि नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, उपदेश और महापरिनिर्वाण से जुड़े प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों का केंद्र है। इस कारण बोधगया, सारनाथ, राजगीर, कुशीनगर और नालंदा जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा भूटानी नागरिकों के लिए विशेष महत्व रखती है।

सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच नियमित रूप से सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, बौद्ध सम्मेलन, कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनियाँ, साहित्यिक कार्यक्रम तथा युवा एवं खेल गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। वर्ष **2025 में बिहार के राजगीर में भूटान सरकार द्वारा निर्मित "रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर"** दोनों देशों की सांस्कृतिक निकटता और बौद्ध विरासत के संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन, योग, आयुर्वेद तथा भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | Website: https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-6 | July – August 2026

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत, भूटान का प्रमुख सहयोगी है। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में भूटानी विद्यार्थी भारत के विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत सरकार **आई.सी.सी.आर (Indian Council for Cultural Relations)**, **नेहरू-वांगचुक छात्रवृत्ति**, **आईटीईसी (Indian Technical and Economic Cooperation)** तथा अन्य छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से भूटानी छात्रों, शोधार्थियों और सरकारी अधिकारियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराती है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तथा लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों का विशेष योगदान रहा है।

दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग में शिक्षक एवं शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा डिजिटल शिक्षा भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, कौशल विकास तथा डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।

इस प्रकार भारत-भूटान के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंध केवल परंपरागत मैत्री तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे **जन-से-जन संपर्क**, ज्ञान-विनिमय, मानव संसाधन विकास तथा साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के माध्यम से दोनों देशों की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

यद्यपि भारत और भूटान के संबंध दक्षिण एशिया में सबसे स्थिर और विश्वासपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में गिने जाते हैं, फिर भी बदलते क्षेत्रीय एवं वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में अनेक चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं। इन चुनौतियों का प्रभाव दोनों देशों की सुरक्षा, आर्थिक सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारी पर पड़ सकता है।

1. चीनका बढ़ता प्रभाव एवं सीमा विवाद: भारत-भूटान संबंधों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चीन की बढ़ती सामरिक एवं कूटनीतिक सक्रियता है। भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद, विशेषकर **डोकलाम, जकारलुंग और पासामलुंग** क्षेत्रों को लेकर, भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील है। 2017 का डोकलाम गतिरोध इस चुनौती का प्रमुख उदाहरण है।

2. आर्थिक निर्भरता: भूटान का व्यापार, ऊर्जा निर्यात और विकास सहायता का बड़ा भाग भारत पर निर्भर है। यद्यपि यह सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी है, फिर भी अत्यधिक आर्थिक निर्भरता भूटान के लिए आर्थिक विविधीकरण की चुनौती प्रस्तुत करती है।

3. जलविद्युत परियोजनाओं में विलंब: भारत-भूटान सहयोग की प्रमुख आधारशिला जलविद्युत परियोजनाएँ हैं, किंतु कई परियोजनाएँ लागत वृद्धि, निर्माण में देरी, तकनीकी कठिनाइयों तथा पर्यावरणीय समस्याओं से प्रभावित हुई हैं। इससे दोनों देशों की आर्थिक अपेक्षाओं पर प्रभाव पड़ता है।

4. जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय जोखिम: हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों का पिघलना, बाढ़, भूस्खलन तथा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी प्राकृतिक

आपदाएँ जलविद्युत परियोजनाओं, अवसंरचना तथा सीमा क्षेत्रों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं।

5. भूटान की संतुलित विदेश नीति: भूटान अपनी संप्रभु विदेश नीति को सुदृढ़ करते हुए अन्य देशों के साथ भी संबंधों का विस्तार कर रहा है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह भूटान की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए पारस्परिक विश्वास और सहयोग को और मजबूत बनाए रखे।

6. सीमा प्रबंधन एवं अवैध गतिविधियाँ: भारत-भूटान की खुली एवं मैत्रीपूर्ण सीमा के कारण तस्करी, अवैध व्यापार, मादक पदार्थों की आवाजाही तथा सीमा-पार अपराध जैसी चुनौतियाँ समय-समय पर सामने आती हैं। इनसे निपटने के लिए दोनों देशों के बीच प्रभावी सीमा प्रबंधन और सुरक्षा समन्वय आवश्यक है।

7. क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती शक्ति प्रतिस्पर्धा, दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक परिस्थितियाँ तथा वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन भारत-भूटान संबंधों के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे परिवेश में दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना होगा।

समग्रतः, इन चुनौतियों के बावजूद भारत और भूटान के संबंध पारस्परिक विश्वास, साझा सुरक्षा हितों तथा विकासात्मक सहयोग पर आधारित हैं। निरंतर संवाद, आर्थिक विविधीकरण, हरित ऊर्जा सहयोग, डिजिटल संपर्क और उच्चस्तरीय कूटनीतिक सहभागिता के माध्यम से इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है।

भविष्य की संभावनाएँ:

भारत और भूटान के संबंध भविष्य में और अधिक व्यापक, बहुआयामी तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने की संभावना रखते हैं। बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की उभरती भू-राजनीति, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने दोनों देशों के सहयोग के नए आयाम खोल दिए हैं। भारत की **"पड़ोसी प्रथम नीति"**, **"पूर्व की तरफ देखो नीति"** तथा **"विकसित भारत @2047"** की परिकल्पना में भूटान एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार के रूप में उभरता है।

ऊर्जा क्षेत्र में जलविद्युत सहयोग भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण संभावनाओं में से एक है। दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर एवं पवन ऊर्जा तथा सीमा-पार विद्युत व्यापार को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ई-गवर्नेंस तथा स्टार्टअप सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और अधिक सुदृढ़ हो सकते हैं।

सामरिक दृष्टि से चीन-भूटान सीमा वार्ता तथा डोकलाम क्षेत्र की संवेदनशीलता भारत-भूटान सुरक्षा सहयोग को भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण बनाएगी। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन तथा रक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल तथा संयुक्त सुरक्षा तंत्र भविष्य में भी द्विपक्षीय सुरक्षा के प्रमुख आधार बने रहेंगे।

व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में सीमा अवसंरचना, रेल संपर्क, सड़क नेटवर्क, बहु-मोडल परिवहन तथा पर्यटन सहयोग आर्थिक विकास को नई गति प्रदान कर सकते हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, अनुसंधान, छात्रवृत्ति तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान दोनों देशों के जन-से-जन संबंधों को और मजबूत करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्यों, जैव विविधता संरक्षण तथा हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण जैसे मुद्दों पर भारत और भूटान का सहयोग वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि दोनों देश परस्पर विश्वास, समानता, संप्रभुता के सम्मान तथा साझा हितों के आधार पर सहयोग को निरंतर आगे बढ़ाते हैं, तो भारत-भूटान संबंध दक्षिण एशिया में स्थिरता, समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग का आदर्श मॉडल बने रहेंगे तथा **विकसित भारत 2047** के लक्ष्य की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

निष्कर्ष:

भारत-भूटान संबंध दक्षिण एशिया के सबसे स्थिर, विश्वासपूर्ण और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक हैं। इन संबंधों की नींव ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा सामरिक समानताओं पर आधारित है, जिसे 1949 की भारत-भूटान मैत्री संधि तथा 2007 के संशोधित समझौते ने और अधिक सुदृढ़ एवं समकालीन स्वरूप प्रदान किया। समय के साथ यह संबंध केवल सुरक्षा और कूटनीति तक सीमित न रहकर आर्थिक विकास, जलविद्युत, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, डिजिटल सहयोग तथा सतत विकास जैसे अनेक क्षेत्रों तक विस्तृत हो गए हैं।

भारत भूटान का सबसे बड़ा विकास साझेदार, प्रमुख व्यापारिक सहयोगी तथा विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार है। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं, आधारभूत संरचना, जलविद्युत परियोजनाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का योगदान उसकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार रहा है। वहीं भूटान ने भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विशेषकर हिमालयी सीमा क्षेत्र की स्थिरता तथा क्षेत्रीय सामरिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डोकलाम संकट जैसे अवसरों ने दोनों देशों के पारस्परिक विश्वास और रणनीतिक सहयोग की मजबूती को स्पष्ट किया है।

यद्यपि चीन का बढ़ता प्रभाव, सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन, जलवायु परिवर्तन तथा भूटान की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता जैसी चुनौतियाँ भविष्य में संबंधों की परीक्षा ले सकती हैं, फिर भी दोनों देशों के बीच विश्वास, संप्रभुता के सम्मान तथा समान हितों पर आधारित सहयोग इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत और भूटान को पारंपरिक सहयोग के साथ-साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कौशल विकास और क्षेत्रीय संपर्क के नए क्षेत्रों में भी साझेदारी को और सुदृढ़ करना होगा।

अंततः कहा जा सकता है कि भारत-भूटान संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के द्विपक्षीय संबंध नहीं हैं, बल्कि दक्षिण एशिया में **विश्वास, समानता, पारस्परिक सम्मान, साझा विकास और रणनीतिक सहयोग** का एक आदर्श मॉडल हैं। यदि दोनों देश इसी भावना के साथ सहयोग को आगे बढ़ाते हैं, तो यह साझेदारी न केवल क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को सुदृढ़ करेगी, बल्कि **विकसित भारत 2047**, भूटान के **Gross National Happiness** आधारित

विकास मॉडल तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. सिंघल एस. सी. (2024), भारत की विदेश नीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन।
2. गांगुली, सुमित (2025), भारत की विदेश नीति पुरवालोकन एवं संभावनाएं, OUP पब्लिकेशन, भारत।
3. मीनाक्षी बंसल (2025), भारत की विदेश नीति के बुनियादी अवधारणा, BFC पब्लिकेशन, भारत।
4. दीक्षित, जे. एन. (2005), भारत की विदेश नीति और उनके पड़ोसी, ज्ञान पब्लिकेशन हाउस।
5. उपाध्याय, भगवत शरण (2014), भारत के पड़ोसी देश, राजपाल एवं संस
6. मीणा पूरण मल, (2020) भारत भूटान संबंध आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम, 2020, Vol.2, Issue. 2, Part B,
7. निशंक रमेश पोखरियाल (2019), खुशियों का देश भूटान मेरी विदेश यात्राएं: तीन, प्रभात प्रकाशन
8. दैनिक जागरण (2026), भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक समझौता।
9. भारत-भूटान संबंध IAS दृष्टि।
10. वर्ल्ड फोकस (Sep 2026), भारत उसके पड़ोसी देश, पीयर रिव्यू रिसर्च जर्नल, अंक-162
11. Khanna, V.N and Kumar Leslie, foreign policy of India, S. Chand Publication Noida.
12. Atwal RavJeet Singh (2026) India’s foreign policy conflict and cooperation.
13. Yadav R.S. (2021), India's foreign policy post code war, Pearson Publication.
14. Miller P. Frederic, Vandom F. Agnes, Mc Brewster John (2020) Bhutan India relation, Alpha script Publication.
15. Debnath sailen (2017), Indo Bhutan relationship modern Times study of bilateral relations, Aayu Publications.
16. Kohali Manorama (1995) India and Bhutan study in interrelation, (1772-1910) Munshi Ram Manohar Lal publishers.
17. http:// www.icwa.in
18. http:// www.orfonline.org
19. http:// www.mfa.gov.in
20. http:// www.indembthimpu.gov.in
21. http:// www.mfa.gov.in